

दिनांक: 28-09-2003

क्रम संख्या: 10,264

मूल्यवर्ग: 50

क्रेता:

किसके लिए:

जी. एस. रेड्डी

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

उप-निबंधक पुत्र: जी. जी. रेड्डी

एपी-सचिवालय, हैदराबाद

पदेन स्टांप विक्रेता

आर.ओ. हैदराबाद

एस.

आर.ओ.एस.आर.नगर

राज्य सहायता समझौता

यह राज्य सहायता समझौता आज दिनांक 30 सितंबर, 2003 को निम्नलिखित के मध्य संपन्न हुआ है:

(1) **आंध्र प्रदेश के राज्यपाल**, परिवहन, सड़क और भवन (बंदरगाह) विभाग के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिनका कार्यालय जे-ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद- 500 022, भारत में स्थित है, और जिन्हें सी. नं. 6786/P1/2002 दिनांक 29 सितंबर, 2003 के तहत इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया है (जिन्हें आगे "आंध्र प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे और जिन्हें आगे परिभाषित किया गया है); और

(2) **हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद - 500 022, भारत में स्थित है (जिन्हें आगे "एचआईएएल" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और हस्तांतरी शामिल होंगे) है।

प्रस्तावना:

क. भारत सरकार ने हवाईअड्डा आधारभूत अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति के तहत, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद के पास शमशाबाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए स्वीकृति और अपना समर्थन प्रदान किया है। भारत

सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को संबोधित अपने पत्र, दिनांक 29 मई 2000 द्वारा यह पुष्टि की है कि बेगमपेट, हैदराबाद में स्थित मौजूदा हवाईअड्डे को सभी नागरिक संचालन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार ने हवाईअड्डे के विकास के लिए दिनांक 23 नवंबर 2000 को एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

- ख. दिसंबर 1999 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम के आधार पर निजी वित्तपोषण के माध्यम से हवाईअड्डा परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। मेसर्स जीएमआर-वासवी बैंगलोर (जिसे बाद में "जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड" नाम दिया गया) ने मेसर्स एमएचबी (मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग्स बरहाद, मलेशिया) के सहयोग से एक कंसोर्टियम बनाया जिसे जीएमआर-एमएचबी कंसोर्टियम कहा गया। इस कंसोर्टियम ने सहमति व्यक्त की कि राज्य सहायता के साथ शमशाबाद में एक नया हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाना और संचालित करना व्यावहारिक है और तदनुसार संयुक्त उद्यम के आधार पर विकसित की जाने वाली परियोजना के लिए बोली लगाई। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, जीएमआर-एमएचबी कंसोर्टियम ("**डेवलपर**") को निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर हवाईअड्डे (जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है) को डिजाइन करने, वित्तपोषित करने, निर्माण करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए चुना गया था (जिसे "**परियोजना**" कहा गया है)।
- ग. यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आंध्र प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास, पर्यटन, यात्री कार्गो आवाजाही और आंध्र प्रदेश राज्य के सामान्य आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास और परियोजना में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है और जीएमआर-एमएचबी कंसोर्टियम को परियोजना के डेवलपर के रूप में नियुक्त करते हुए जी.ओ. एमएस नंबर 130 दिनांक 26 जुलाई 2003 जारी किया है। पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि हवाई अड्डों के कार्यान्वयन और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा संशोधित किया गया है।
- घ. परियोजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, एचआईएल को आंध्र प्रदेश राज्य में एक सीमित देयता कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। डेवलपर और आंध्र प्रदेश सरकार का इरादा एआई के साथ एचआईएल में शेयरधारक (जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है) बनने का है। एचआईएल, भारत सरकार के साथ एक रियायत समझौते ("**रियायत समझौता**") में प्रवेश करेगा, जिसके द्वारा एचआईएल को परियोजना को लागू करने और संचालित करने की रियायत प्रदान की जाएगी।
- ङ. यह परियोजना केवल आंध्र प्रदेश सरकार की राज्य सहायता (जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है) के साथ ही व्यावहारिक है, और भारत सरकार एवं आंध्र प्रदेश सरकार दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की और इसे स्वीकार किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन तथा इसके एवं इसकी सुविधाओं के संचालन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक और निरंतर समर्थन, कार्रवाइयों और कुछ अधिकारों व प्राधिकरणों की स्वीकृति की आवश्यकता है, जो एचआईएल द्वारा संसाधनों (वित्तीय संसाधनों सहित) जुटाने और रियायत समझौते के तहत एचआईएल के दायित्वों के निष्पादन के लिए पूर्व-शर्तें हैं। इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस

समझौते में उल्लिखित अनुसार एचआईएल को राज्य सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

इसलिए अब, पक्षकारों के पारस्परिक वचनों के विचारार्थ, जिसकी पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और अन्य श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य प्रतिफल के आधार पर, पक्षकार निम्नलिखित पर सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, इसकी प्रस्तावना सहित, निम्नलिखित शब्दों, अभिव्यक्तियों और संक्षिप्त रूपों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"एआई" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआई) होगा, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003, भारत में स्थित है।

"समझौता" का अर्थ यह राज्य सहायता समझौता है जिसे समय-समय पर संशोधित और रूपांतरित किया जा सकता है।

"हवाईअड्डा" का अर्थ आंध्र प्रदेश, भारत में हैदराबाद के पास शमशाबाद में एचआईएल द्वारा निर्मित और संचालित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है और इसमें इसकी सभी इमारतें, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां, वैमानिकी और गैर-वैमानिकी तथा हवाईअड्डा केंद्रित गतिविधियां शामिल हैं, और परिस्थिति अनुसार समय-समय पर इसका कोई भी विस्तार बिना किसी सीमा के शामिल है।

"हवाईअड्डा ज़ोनिंग क्षेत्र" का अर्थ जीओ एमएस नंबर 352एमए दिनांक 30 जुलाई 2001 के तहत अधिसूचित विशेष विकास क्षेत्र अधिसूचना के रूप में हवाईअड्डे के भीतर, उससे सटे और उसके आसपास का क्षेत्र है।

"कारोबारी दिवस" का अर्थ ऐसा दिन है जिस दिन मुंबई या हैदराबाद, भारत में सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लेन-देन के लिए बैंक आमतौर पर खुले रहते हैं, और "कारोबारी दिनों" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

"कानून में बदलाव" का अर्थ इस समझौते की तिथि के बाद से लेकर वाणिज्यिक परिचालन तिथि की बीसवीं वर्षगांठ तक निम्नलिखित में से किसी का घटित होना है:

क. किसी नए कानून का अधिनियमन या किसी नए निर्देश या नीति को जारी करना या कार्यान्वयन या किसी भी सरकारी एजेंसी के किसी मौजूदा कानून या निर्देश या नीति का संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता या निरसन अथवा किसी अदालत या न्यायाधिकरण का कोई निर्णय या आदेश जो अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर और विदेश यात्रा कर के लिए उपलब्ध छूट, उपयोगकर्ता विकास शुल्क वसूलने की क्षमता, हवाई यातायात नियंत्रण, संचार, मौसम विज्ञान और/या सुरक्षा सेवाओं पर सेवा कर की दर में परिचय या वृद्धि, आंध्र प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या जीओएम 130 दिनांक 26 जुलाई, 2003 के तहत उपलब्ध

हवाईअड्डे की निर्माण अवधि के दौरान आवश्यक सभी इनपुट पर बिक्री कर से (i) छूट; (ii) पहली बिक्री/हस्तांतरण के लिए स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट और (iii) हवाईअड्डे की निर्माण अवधि के दौरान गौण खनिजों पर सेनियोरेज शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट को हटाने या वापस लेने, या आंध्र प्रदेश राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध लाभों को हटाने या वापस लेने को प्रभावित करता हो;

ख. किसी नियामक या सरकारी एजेंसी द्वारा टैरिफ को विनियमित करने, निरस्त करने या संशोधित करने वाली कोई भी अधिसूचना जिसका प्रभाव हवाईअड्डे के वैमानिकी राजस्व को कम करना हो;

ग. हवाईअड्डे से संबंधित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी मंजूरी की स्वीकृति की तिथि के बाद, ऐसी मंजूरी से जुड़ी शर्तों और निबंधनों में बदलाव या किसी नई शर्तों या निबंधनों का जुड़ना या ऐसी मंजूरी का आंशिक या पूर्ण रूप से लागू न रहना;

घ. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कोई भी चूक या कृत्य जो इस समझौते के तहत एचआईएएल के अधिकारों को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

"नागर विमानन गतिविधि" का अर्थ सभी नागर विमानन गतिविधियां हैं, चाहे वह अनुसूचित हो या गैर-अनुसूचित, और चार्टर्ड, चाहे वह यात्रियों, कार्गो, मेल, कूरियर और अन्य यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, घरेलू और/या स्थानीय हवाई सेवा हो और सभी नागरिक और वाणिज्यिक विमानन संबंधी सेवाएं जैसे इंजीनियरिंग, रखरखाव, ग्राउंड सपोर्ट और सेवा, विमानन प्रशिक्षण और विमानन शिक्षण व ट्यूशन उद्देश्य हों।

"मंजूरी" का अर्थ किसी भी प्रकार की सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, सत्तारूढ़, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकरण या अनुमति है जिसे परियोजना के संबंध में समय-समय पर सरकारी एजेंसी से प्राप्त किया जाना और/या प्रदान किया जाना आवश्यक है।

"वाणिज्यिक परिचालन तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस दिन हवाईअड्डे के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत होती है।

"रियायत समझौता" का अर्थ परियोजना के संबंध में भारत सरकार (भारत सरकार) और एचआईएएल द्वारा हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाने वाला रियायत समझौता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

"डेवलपर" का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना ख में परिभाषित किया गया है।

"भेदभावपूर्ण कार्रवाई" का वही अर्थ है जो खंड 3 में दिया गया है।

"डीपीआर" का अर्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है जिसे डेवलपर द्वारा व्यावहारिक रूप से परियोजना के चरण-I के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया जाना है, और आंध्र प्रदेश सरकार तथा एचआईएएल के अन्य शेयरधारकों के मध्य सहमति व्यक्त की जानी है एवं एचआईएएल द्वारा अपनाया जाना है।

"वित्तीय समापन" का अर्थ वह तिथि है जिस दिन वित्तपोषण समझौते, इक्विटी दस्तावेज (यदि कोई हो) और ऋण के संबंध में दस्तावेज (यदि कोई हो) प्रभावी हो जाते हैं और एचआईएएल को इसके तहत प्रतिबद्ध धन की पहली निकासी की पहुंच प्राप्त हो जाती है।

"वित्तपोषण समझौते" का अर्थ सामूहिक रूप से वे समझौते, दस्तावेज और अन्य दस्तावेज हैं जो एचआईएएल और ऋणदाताओं के मध्य दर्ज किए गए हैं, जिनके तहत एचआईएएल को ऋण वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। "वित्तपोषण समझौता" शब्द में यह समझौता या कोई अन्य समझौता शामिल नहीं होगा जिसके द्वारा या जिसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार, एचआईएएल को आंध्र प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत होता है।

"आंध्र प्रदेश सरकार " का अर्थ आंध्र प्रदेश सरकार है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड, एजेंसी या अन्य साधन शामिल हैं, जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी कानून, नियम और विनियम के तहत विधिवत गठित प्राधिकरण वाले उनके संबंधित उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।

"आंध्र प्रदेश सरकार चूक राशि" का अर्थ अनुलग्नक 1 के अनुसार गणना की गई राशि है।

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार है, जिसमें भारत सरकार का कोई भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड, एजेंसी या अन्य साधन शामिल हैं, जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी कानून, नियम और विनियम के तहत विधिवत गठित प्राधिकरण वाले उनके संबंधित उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।

"सरकारी एजेंसी" का अर्थ भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार या सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड, निकाय, ब्यूरो, एजेंसी, प्राधिकरण या भारत सरकार और या आंध्र प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी कंपनी, साधन, अदालत या अन्य न्यायिक या प्रशासनिक निकाय है, चाहे वह केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर का हो, जिसका पक्षकारों, हवाईअड्डे और या इसके किसी भी हिस्से की सुविधाओं पर या इस समझौते के तहत या इसके अनुसार पक्षकारों की सभी या किसी भी सेवा या दायित्वों के निष्पादन पर क्षेत्राधिकार है।

"ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति" का अर्थ केंद्रीय बजट 2002-2003 में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित नीति है।

"एचआईएएल" का अर्थ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो भारत के कानूनों के अनुसार निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में स्थित है, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ और जिसमें इसके प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी और या इसके अनुमति प्राप्त हस्तांतरी शामिल होंगे।

"एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना" का अर्थ है:

क. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस समझौते और या भूमि पट्टा समझौते का कोई भी उल्लंघन या चूक जो इस समझौते के तहत एचआईएएल के अधिकारों को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है; और या

- ख. कानून में कोई भी ऐसा बदलाव जो इस समझौते के तहत एचआईएएल के अधिकारों को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है; और या
- ग. कोई भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई करना जो इस समझौते के तहत एचआईएएल के अधिकारों को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है; और या
- घ. एचआईएएल को उसके किसी भी ठेकेदार, सेवक या एजेंट के लिए आवश्यक किसी भी मंजूरी को देने में विफलता, उसे रद्द करना या उसमें कोई नई शर्त जोड़ना; और या
- ङ. स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, संपत्ति कर, अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर और विदेशी यात्रा कर से छूट, और उपयोगकर्ता विकास शुल्क वसूलने की क्षमता से संबंधित कर के संबंध में कोई नया कानून बनाने या नया निर्देश जारी करने या लागू करने में विफलता।

"भूमि" का अर्थ लगभग 5000 एकड़ (पांच हजार एकड़) माप वाली वह निकटवर्ती भूमि है जिसे भूमि पट्टा समझौते में अधिक पूर्ण रूप से परिभाषित और वर्णित किया गया है, जिस पर, जिसके नीचे और जिसके ऊपर हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

"भूमि पट्टा समझौता" का अर्थ आंध्र प्रदेश सरकार और एचआईएएल के मध्य किया गया भूमि पट्टा समझौता है, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने एचआईएएल को भूमि में पट्टेदार अधिकार प्रदान किया है।

"कानून" का अर्थ इस तिथि तक लागू और प्रभावी सभी प्रासंगिक कानून हैं जिन्हें इसके बाद भारत में प्रख्यापित या लागू किया जा सकता है, जिसमें प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक आदेश, निर्णय, डिक्री, निर्देश, व्यादेश, रिट या अदालत के आदेश शामिल हैं जो इस समझौते के अस्तित्व के दौरान लागू और प्रभावी हो सकते हैं।

"ऋणदाता" का अर्थ वित्तीय संस्थान, बैंक, फंड, लीजिंग कंपनियां या ट्रस्ट हैं जो परियोजना की लागत के ऋण घटक का प्रावधान या पुनर्वित्त करते हैं (जिसमें गारंटी, जोखिम भागीदारी सुविधा, हेज, टेक-आउट सुविधा और क्रेडिट वृद्धि के अन्य रूप शामिल हैं) और इसमें हवाईअड्डे और या उसके विस्तार की लागत को पूरा करने के लिए एचआईएएल द्वारा जारी डिबेंचर, बॉन्ड या अन्य ऋण प्रतिभूतियों के धारकों के लिए ट्रस्टी के ग्राहक शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणदाताओं में वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो एचआईएएल में डेवलपर द्वारा लाए जाने वाले इक्विटी योगदान का वित्तपोषण करते हैं।

"ग्रहणाधिकार" का अर्थ कोई भी बंधक, गिरवी, ट्रस्ट डीड, दृष्टिबंधक, दूसरों का अधिकार, दावा, सुरक्षा हित, भार, बोझ, स्वामित्व दोष, स्वामित्व प्रतिधारण समझौता, पट्टा, उप-पट्टा, लाइसेंस, अधिभोग समझौता, सुखाचार, प्रसंविदा, शर्त, अतिक्रमण, मतदान ट्रस्ट समझौता, हित, विकल्प, प्रथम प्रस्ताव का अधिकार, बातचीत या अस्वीकृति का अधिकार, प्रॉक्सी, ग्रहणाधिकार, प्रभार, विचाराधीन वाद या किसी भी प्रकृति का अन्य प्रतिबंध या सीमाएं हैं, जिसमें किसी भी अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले ग्रहणाधिकार शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

"पक्षकार" का सामूहिक रूप से अर्थ आंध्र प्रदेश सरकार और एचआईएएल होगा, और "पक्षकार" शब्द का व्यक्तिगत रूप से अर्थ आंध्र प्रदेश सरकार और एचआईएएल होगा।

"परियोजना" का वही अर्थ होगा जो इसे प्रस्तावना ख में सौंपा गया है।

"परियोजना समझौते" का सामूहिक रूप से अर्थ यह समझौता, रियायत समझौता, उपकरण, निर्माण और खरीद समझौता, संचालन और प्रबंधन समझौते, संचार और नेविगेशन सेवाएं और हवाई यातायात प्रबंधन समझौते, भूमि पट्टा समझौता, सेवा समझौते और 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य का कोई भी अन्य महत्वपूर्ण अनुबंध है जो परियोजना के संबंध में एचआईएएल द्वारा दर्ज किया जाना है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

"शेयरधारक" का अर्थ एचआईएएल में इक्विटी शेयर रखने वाले व्यक्ति हैं।

"राज्य सहायता" का अर्थ इस समझौते में निर्धारित अनुसार सहायता और सहयोग का अनुदान या प्रावधान है।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- क. इस समझौते के उद्देश्य के लिए, जहां संदर्भ अनुमति देता है, (i) एकवचन में बहुवचन शामिल माना जाएगा और इसका विपरीत भी, (ii) पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शामिल माना जाएगा और इसका विपरीत भी, और (iii) "शामिल है" और "शामिल करते हुए" शब्दों का बिना किसी सीमा के अर्थ लगाया जाएगा।
- ख. "व्यक्ति" के संदर्भों में, जहां संदर्भ अनुमति देता है, प्राकृतिक व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों और संघों के संदर्भ शामिल होंगे, चाहे वे निगमित हों या नहीं या कोई अन्य संगठन या इकाई जिसमें कोई सरकारी या राजनीतिक उप-विभाग, मंत्रालय, विभाग या उसकी एजेंसी शामिल हो।
- ग. खंडों, प्रस्तावनाओं या अनुलग्नकों के संदर्भ इस समझौते के खंडों, प्रस्तावनाओं और अनुलग्नकों के संदर्भ हैं। अनुलग्नक इस समझौते का एक अभिन्न अंग होंगे।
- घ. किसी वैधानिक प्रावधान का कोई भी संदर्भ ऐसे प्रावधान और किसी भी अधीनस्थ विधान को शामिल करेगा जो तत्समय लागू है और जैसा कि समय-समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित किया गया है, जहां तक ऐसा संशोधन या पुनः अधिनियमन इस समझौते द्वारा कवर किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू होने में सक्षम है।
- ङ. शीर्षक और उप-शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और इस समझौते के निर्माण और व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।
- च. खंड 1.1 में परिभाषित शब्दों के अलावा, कुछ अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द इस समझौते में अन्यत्र परिभाषित किए गए हैं और जब भी ऐसे शब्दों का उपयोग इस समझौते में किया जाता है, तो उनके संबंधित परिभाषित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अन्यथा अपेक्षित न करे।
- छ. महीने के किसी भी संदर्भ का अर्थ कैलेंडर महीने के संदर्भ से होगा। इस समझौते में "दिन" का संदर्भ "कारोबारी दिवस" का संदर्भ होगा, केवल खंड 3.1 को छोड़कर।
- ज. यह समझौता इसके निष्पादन की तिथि से लागू होगा, शर्त यह है कि इस समझौते की शर्तों के अनुसार अंतरिम ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देने के आंध्र प्रदेश सरकार के दायित्व वित्तीय समापन पर और निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते के ट्रस्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद शुरू होंगे कि वित्तीय समापन हो गया है।

2. आंध्र प्रदेश सरकार सहायता

2.1 सहायता

आंध्र प्रदेश सरकार स्वीकार करती है और सहमत होती है कि यह परियोजना केवल आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से ही व्यावहारिक है, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को किफायती और समय पर पूरा करने में सहायता करना है, और इसलिए वह एचआईएएल को इस समझौते में निर्धारित राज्य सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई है।

2.2 भूमि

आंध्र प्रदेश सरकार सहमत होती है और वारंटी देती है कि वह भूमि पट्टा समझौते के अनुसार एचआईएएल को वित्तीय समापन से कम से कम 1 महीने पहले पूरी भूमि का भौतिक, खाली, शांतिपूर्ण, बाधा मुक्त, भार मुक्त कब्जा किसी भी और सभी ग्रहणाधिकार से मुक्त प्रदान करेगी और सौंपेगी। एचआईएएल को कब्जा सौंपने की तिथि पर एचआईएएल को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि बिना किसी उच्च तनाव बिजली लाइनों, बिना किसी ग्रामीण सड़क डायवर्सन और किसी भी पर्यावरणीय खतरों से मुक्त होगी।

2.3 वित्तीय और राजकोषीय सहायता

(क) अग्रिम विकास कोष अनुदान

- (i) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल को 107 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम विकास कोष अनुदान प्रदान करेगी। अग्रिम विकास कोष अनुदान पर किसी भी परिस्थिति में ब्याज का भुगतान लागू नहीं होगा और न ही यह पुनर्भुगतेय होगा।
- (ii) अग्रिम विकास कोष अनुदान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एचआईएएल को तीन समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा, और पहली किस्त वित्तीय समापन पर निकाली जाएगी। प्रत्येक किस्त का भुगतान निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में किया जाएगा जिसे वित्तपोषण समझौतों के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा।
- (iii) अग्रिम विकास कोष अनुदान की पहली किस्त का भुगतान निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में किया जाएगा, जिसे वित्तीय समापन पर नकद में वित्तपोषण समझौते के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार अग्रिम विकास कोष अनुदान की शेष राशियों के लिए वित्तीय समापन से पहले एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त साख पत्र खोलेगी, जिसे अनुलग्नक 2 के अनुसार निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में निकाला जाएगा और या हवाईअड्डे के निर्माण की प्रगति के अनुसार धन की आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार बाद की तिथि पर निकाला जाएगा।

(ख) ब्याज मुक्त ऋण

- (i) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल को 3,15,00,00,000 रुपये (तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपये) की राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। ब्याज मुक्त ऋण पर किसी भी परिस्थिति में ब्याज पुनर्भुगतान लागू नहीं होगा। आंध्र प्रदेश सरकार सहमत होती है और स्वीकार करती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने पर ब्याज मुक्त ऋण को आनुपातिक रूप से ऊपर या नीचे समायोजित किया जा सकता है, यदि यह निर्धारण किया जाता है कि परियोजना लागत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऐसा

आनुपातिक समायोजन आवश्यक है ताकि इक्विटी की आंतरिक प्रतिफल दर को 18.33 प्रतिशत पर बनाए रखा जा सके।

- (ii) ब्याज मुक्त ऋण अनुलग्नक 2 में दी गई अनुसूची के अनुसार निकाला जाएगा। प्रत्येक किस्त का भुगतान निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में किया जाएगा जिसे वित्तपोषण समझौतों के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा।
- (iii) आंध्र प्रदेश सरकार सहमत होती है कि ब्याज मुक्त ऋण को पांच समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसकी पहली किस्त वाणिज्यिक परिचालन तिथि की 16वीं वर्षगांठ पर होगी।
- (iv) ब्याज मुक्त ऋण की पहली किस्त का भुगतान निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में किया जाएगा जिसे वित्तीय समापन पर नकद में वित्तपोषण समझौतों के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशियों के लिए वित्तीय समापन से पहले एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त साख पत्र खोलेगी, जिसे अनुलग्नक 2 के अनुसार निर्माण आय ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते में निकाला जाएगा और या हवाईअड्डे के निर्माण की प्रगति के अनुसार फंड की आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार बाद की तिथि पर निकाला जाएगा।
- (v) एचआईएल वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद 16वें वर्ष पर या उसके बाद और वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद 20वें वर्ष के पूरा होने पर या उससे पहले ब्याज मुक्त ऋण की चुकौती पूरी करने का वचन देता है, चाहे वरिष्ठ ऋणदाताओं के ऋण का भुगतान किया गया हो या नहीं।
- (vi) किसी भी वर्ष के दौरान जिसमें कोई ब्याज मुक्त ऋण पुनर्भुगतान किस्त या बकाया ब्याज मुक्त ऋण पुनर्भुगतान किस्त देय और देय योग्य है, एचआईएल तब तक किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं करेगा जब तक कि उस विशेष वर्ष के लिए ऐसी ब्याज मुक्त ऋण पुनर्भुगतान किस्त और किसी भी पिछली बकाया ब्याज मुक्त ऋण पुनर्भुगतान किस्त का भुगतान न कर दिया गया हो।

(ग) छूट

आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम, 2001 के तहत राज्य सहायता की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार केवल निम्नलिखित छूट प्रदान करेगी:

- (i) परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक सभी इनपुट पर बिक्री कर की छूट।
- (ii) सरकार से डेवलपर को भूमि के पहले हस्तांतरण पर और राज्य में पंजीकृत परियोजना समझौतों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट।
- (iii) निर्माण अवधि के दौरान सेनियोरेज शुल्क यानी गौण खनिजों पर उपकर के भुगतान से छूट।

आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डे की भूमि को 'निर्दिष्ट प्राधिकरण' या स्वतंत्र स्थानीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करने के लिए सभी कदम उठाएगी।

2.4 बाह्य अवसंरचना

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुसार,

(क) चार लेन पहुंच मार्ग

आंध्र प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से हवाईअड्डे की पश्चिमी सीमा तक और श्रीशैलम राज्य राजमार्ग से हवाईअड्डे की पूर्वी सीमा तक चार लेन का पहुंच मार्ग प्रदान करेगी।

(ख) जल आपूर्ति

आंध्र प्रदेश सरकार निर्माण और हवाईअड्डे के वाणिज्यिक संचालन के दौरान हवाईअड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेट्रो वाटर सीवेज बोर्ड या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के माध्यम से हवाईअड्डे की सीमा तक निरंतर स्वच्छ और पर्याप्त पानी की आपूर्ति करेगी। जल शुल्क का भुगतान एचआईएएल द्वारा लागू दरों पर किया जाएगा।

यह परिकल्पना की गई है कि वाणिज्यिक संचालन के दौरान हवाईअड्डा टर्मिनलों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग आठ लाख लीटर प्रति दिन (या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के बाद संशोधित या वैध की जाने वाली ऐसी अन्य मात्रा) की आवश्यकता होगी।

(ग) बिजली आपूर्ति

आंध्र प्रदेश सरकार निर्माण और हवाईअड्डे के वाणिज्यिक संचालन के दौरान एचआईएएल के स्टेप डाउन सब-स्टेशन तक हवाईअड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाईअड्डे को बिजली और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगी। बिजली और ऊर्जा शुल्क का भुगतान एचआईएएल द्वारा लागू दरों पर किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश सरकार अपने खर्च पर हवाईअड्डे पर एचआईएएल के स्टेप-डाउन सब-स्टेशन तक बिजली और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए दो स्वतंत्र स्रोतों से पूर्ण बुनियादी ढांचे को स्थापित, चालू और उपलब्ध कराएगी, बशर्ते हवाईअड्डे की सीमा से एचआईएएल के स्टेप डाउन सब-स्टेशन तक उपर्युक्त कमीशनिंग और बुनियादी ढांचे की लागत एचआईएएल द्वारा वहन की जाएगी। यह परिकल्पना की गई है कि वाणिज्यिक संचालन के दौरान बिजली पारेषण लाइनों, ट्रांसफॉर्मर, सब-स्टेशनों और सभी संबंधित नागरिक कार्यों के साथ कम से कम छह मेगावाट की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले कम से कम 11 केवी उच्च तनाव की आवश्यकता होगी (या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने पर संशोधित या वैध की जाने वाली ऐसी अन्य आवश्यकता)।

(घ) रेलवे कनेक्शन

आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डे के निर्माण और संचालन की आवश्यकता के अनुसार, हैदराबाद या सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से हवाईअड्डे के यात्री और कार्गो टर्मिनलों को जोड़ने वाले हवाईअड्डे के लिए एक उपयुक्त रेलवे कनेक्शन का प्रावधान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर सहमत होती है। आंध्र प्रदेश सरकार सभी संबंधित एजेंसियों, निकायों, प्राधिकरणों के साथ समन्वय में भूमि अधिग्रहण, रेलवे लाइन बिछाने, रेलवे स्टेशन स्थापित करने और रेलवे को

संचालित करने के लिए आवश्यक सभी संबद्ध बुनियादी ढांचे सहित सभी कार्रवाई सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर करने के लिए सहमत होती है।

(ड°) राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के हिस्से का रूपांतरण

आंध्र प्रदेश सरकार सभी सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में हवाईअड्डे तक यातायात की सुगम आवाजाही के लिए हैदराबाद को शमशाबाद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को 6-लेन एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए, हवाईअड्डे के निर्माण और संचालन की आवश्यकता के अनुसार, सर्वोत्तम प्रयास करने पर सहमत होती है।

(च) सामान्य सार्वजनिक परिवहन

आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवाईअड्डे की सीमा तक और वहां से सुरक्षित, कुशल और नियमित सामान्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का प्रावधान प्रदान करेगी और प्राप्त करेगी।

2.5 पहुंच अधिकार

- (क) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल को निरंतर आधार पर और समयबद्ध तरीके से,
- (i) भूमि पट्टा समझौते और रियायत समझौते के अनुसार पहुंच के सभी अधिकार;
 - (ii) हवाईअड्डे के बाहर की जाने वाली सभी गतिविधियों को करने के लिए और हवाईअड्डे के बाहर स्थित होने वाले सभी प्रतिष्ठानों का निर्माण और रखरखाव करने के लिए आवश्यक सभी संपत्ति अधिकार और मंजूरियां; और (iii) ऐसे अन्य पहुंच अधिकार और या संपत्ति अधिकार, जो परियोजना समझौतों के तहत और या हवाईअड्डे के लिए एचआईएएल या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा आवश्यक हो सकते हैं, प्रदान करने या प्रदान करने की व्यवस्था करने पर सहमत होती है।
- (ख) आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डे और उसकी सभी सुविधाओं की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात के सुचारू प्रवाह और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि आंध्र प्रदेश सरकार और या सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई रुकावट पैदा न की जाए या न बने, सिवाय उन मामलों के जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारण या राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए ऐसी रुकावटें आवश्यक हों।

3. सामान्य सहायता

3.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति

आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करेगी या समीक्षा करवाएगी, और प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर टिप्पणी करेगी, और आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल को एक हस्ताक्षरित प्रति लौटाकर अपनी स्वीकृति की सूचना दे सकती है। यदि आंध्र प्रदेश सरकार ऐसी अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति या टिप्पणियां या अवलोकन देने में विफल रहती है, तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल के साथ अपनी टिप्पणियों या अवलोकनों पर चर्चा करेगी और यदि पक्षकार यह मानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार की किसी भी टिप्पणी या अवलोकन के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने की आवश्यकता

है, तो संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आंध्र प्रदेश सरकार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीस दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति की सूचना देने में विफल रहती है, तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।

3.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत प्रतिपूर्ति

आंध्र प्रदेश सरकार सहमत होती है कि यदि वित्तीय समापन 1 जनवरी 2005 को या उससे पहले या ऐसी अन्य तिथि को नहीं होता है जो पक्षकारों के मध्य पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है, और या परियोजना को छोड़ दिया जाता है, तो वह डेवलपर और या एचआईएएल को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और या उसे पूरा करने से संबंधित सभी लागतों की प्रतिपूर्ति करेगी।

3.3 पुनर्वास लागत

आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डे के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी भी प्रभावित और या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वसन के लिए अपने खर्च पर पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जिसमें किसी भी गांव, झोपड़ियों, मकानों और कॉलोनीयों के पुनर्वसन के संबंध में शामिल है, और आंध्र प्रदेश सरकार एतद्वारा एचआईएएल, उनके संबंधित अधिकारियों, सलाहकारों, एजेंटों, सेवकों और या कर्मचारियों की मांग पर उन सभी और किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई, कार्यवाही और देनदारियों से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और उन्हें सुरक्षित रखने का वचन देती है जो भूमि अधिग्रहण और या पट्टे और या एचआईएएल को भूमि के हस्तांतरण के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

3.4 मौजूदा कानूनों के तहत लाभ

आंध्र प्रदेश सरकार स्वीकार करती है और सहमत होती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित मौजूदा कानून से मिलने वाली किसी भी प्रकृति की सभी छूट और लाभ एचआईएएल को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि लागू कानून के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए एचआईएएल की सहमति के अधीन होंगे।

3.5 समकक्ष व्यवहार

आंध्र प्रदेश सरकार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने और अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाने के लिए सहमत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंध्र प्रदेश सरकार कोई ऐसी कार्रवाई या कार्रवाइयों का संयोजन न करे जिसका प्रभाव भेदभावपूर्ण हो और जो डेवलपर और या एचआईएएल के साथ भारत के किसी भी अन्य हवाईअड्डा संचालक की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार करे या हवाईअड्डे के साथ भारत में किसी भी अन्य हवाईअड्डे या परियोजना की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार करे (भेदभावपूर्ण कार्रवाई)।

3.6 कार्यों का समन्वय

आंध्र प्रदेश सरकार सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने पर सहमत होती है कि सभी कार्यों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ऐसे

अन्य कार्यों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव और हवाईअड्डा संचालन के साथ समन्वित और एकीकृत किया जाए, और परियोजना के संबंध में किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ परामर्श, संपर्क, सहयोग करेगी और सामंजस्य स्थापित करके काम करेगी, जिसमें संयुक्त कार्यक्रमों, विधि विवरणों, समन्वय आरेखों और किसी भी विनिर्देशों की तैयारी शामिल है।

3.7 कार्रवाइयां

शेयरधारकों और ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले निवेश को मान्यता देते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार अपनी शक्ति के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि उसके या उसकी किसी भी एजेंसी द्वारा कोई कदम या कार्रवाई (चाहे किसी कृत्य या चूक के माध्यम से) न उठाई जाए जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों या ऋणदाताओं को हवाईअड्डे में उनके निवेश या आर्थिक हित से वंचित या पर्याप्त रूप से वंचित किया जाता है या होगा। आंध्र प्रदेश सरकार वचन देती है कि वह अपनी शक्ति के भीतर ऐसा कुछ नहीं करेगी या ऐसा कुछ करने में विफल नहीं होगी, जो:

क. परियोजना समझौतों और या वित्तपोषण समझौतों के अनुसार डेवलपर और या एचआईएएल द्वारा अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन का कारण बने, योगदान दे या अन्यथा उत्पन्न करे;

ख. परियोजना समझौतों के तहत या किसी भी कानून या मंजूरी के अनुसार एचआईएएल के किसी भी अधिकार, पात्रता या अन्य लाभों के नुकसान या कमी का कारण बने या पूर्वाग्रह पैदा करे।

3.8 परियोजना मंजूरी

(क) आंध्र प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एचआईएएल द्वारा आवेदन किए जाने पर, या वित्तपोषण समझौतों के अनुसार ऋणदाताओं या उनके संबंधित ठेकेदार, सेवकों या एजेंटों या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, हवाईअड्डे के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी मंजूरियां या विस्तार और या नवीनीकरण जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने हैं, वे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह से दिए जाएं जो परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों के साथ एचआईएएल के अनुपालन को सुनिश्चित करे। आंध्र प्रदेश सरकार:

(i) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत सभी आंध्र प्रदेश सरकार स्तर की मंजूरियां प्रदान करेगी और सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर, सभी भारत सरकार स्तर की मंजूरियां प्राप्त करेगी।

(ii) जब भी विदेशी एयरलाइनों द्वारा आवेदन किया जाए, तो मंजूरियां प्राप्त करने के लिए और हवाईअड्डे से अपनी सेवाएं संचालित करने के लिए विदेशी एयरलाइनों को किसी भी हवाई सेवा समझौतों के तहत द्विपक्षीय अधिकार देने के लिए भारत सरकार के सभी विभागों, निकायों, अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने पर सहमत होती है।

(iii) एचआईएएल द्वारा आवेदन किए जाने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाईअड्डा सेवाओं, कार्यों या किसी भी बुनियादी ढांचे, बिजली और पानी की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध से मुक्त है, आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम,

1968 या किसी अन्य कानून के तहत हवाईअड्डे को 'आवश्यक सेवा' घोषित करने पर अनुकूल रूप से विचार करने और जांच करने के लिए सहमत होती है।

(iv) हवाईअड्डे के लिए ज़ोनिंग आवश्यकताओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहमत होती है, जिन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार हवाईअड्डा ज़ोनिंग क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में सभी विकासात्मक गतिविधियों के विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए सहमत होती है और सुरक्षा और संरक्षा के उद्देश्यों के लिए हवाईअड्डा सुरक्षा कीप और हवाईअड्डे के ज़ोनिंग के लिए जिम्मेदार होगी।

(ग) एचआईएएल का प्रतिनिधित्व हैदराबाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या हैदराबाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी उत्तराधिकारी में प्राधिकरण के बोर्ड में एक पद के माध्यम से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एचआईएएल के पास राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन बोर्ड में कम से कम एक सदस्य हो, जिसका हवाईअड्डे पर यात्री आवाजाही पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

3.9 अन्य सहयोग

(क) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल को विभिन्न शुल्क या शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए और विमान अधिनियम 1934 और इसके तहत सभी नियमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 और इसके तहत सभी नियमों के तहत व्यवसाय करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने पर सहमत होती है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल द्वारा परिकल्पित समय सीमा के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए एचआईएएल द्वारा आवश्यक सभी सहयोग प्रदान करने पर सहमत होती है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर सहमत होती है:

(i) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति को लागू करने की प्रतिबद्धता।

(ii) हवाईअड्डा संचालकों को शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।

(iii) हवाईअड्डे और या हवाईअड्डे के वाणिज्यिक संचालन के लिए आवश्यक मंजूरीयां प्रदान करना जो समय-समय पर आवश्यक हों।

(iv) संचार और नेविगेशन सेवाएं और हवाई यातायात प्रबंधन समझौता और मौसम संबंधी समझौते का कार्यान्वयन।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल की किसी भी संपत्ति जो हवाईअड्डे से संबंधित है या सीधे उससे प्राप्त हुई है, या एचआईएएल द्वारा जारी किए गए किसी भी शेयर या शेयरों में परिवर्तनीय अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, जब्ती, अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, अनिवार्य विनिवेश की मांग या राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी और अपनी शक्ति

के भीतर सभी कदम उठाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसा न करे।

(ड°) आंध्र प्रदेश सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जो रियायत समझौते की समाप्ति के किसी भी आधार को जन्म देने या गठित करने में सक्षम हो।

(च) आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा लगाए गए रियायत समझौते के तहत रियायत शुल्क के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगी, यदि कोई हो। वित्तीय समापन के अंत में, इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा और आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल पर पड़ने वाले प्रभाव को उचित रूप से कवर करेगी।

4. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकारोक्ति, सहायता और सहयोग

(क) आंध्र प्रदेश सरकार स्वीकार करती है और सहमत होती है कि एचआईएएल के पास परियोजना समझौतों के अनुसार हवाईअड्डे का स्वामित्व, विकास, डिजाइन, वित्त पोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव का विशेष अधिकार है और इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार रियायत समझौते, वित्तपोषण समझौतों और संबंधित परियोजना समझौतों को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए सहमत होती है, और एचआईएएल द्वारा उक्त समझौतों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में यथोचित रूप से अनुरोध की गई सहायता प्रदान करेगी।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार रियायत समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह से समर्थन करेगी जहाँ तक ऐसा समर्थन उसकी शक्ति के भीतर है, जो यह प्रदान करेगा:

(i) हैदराबाद या सिकंदराबाद में और रियायत समझौते में निर्दिष्ट यातायात की मात्रा तक और अवधि के लिए समग्र दूरी के भीतर घरेलू और या अंतर्राष्ट्रीय यातायात की सेवा करने वाले हवाईअड्डे में किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे के विकास, सुधार या उन्नयन को भारत सरकार द्वारा स्थापित या अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) भारत सरकार डिंडीगुल और हकीमपेट में मौजूदा स्थलों या हवाई क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं या ऐसे स्थलों में या उनके ऊपर स्थित किसी भी सुविधा को किसी भी नागर विमानन गतिविधि के लिए उपयोग करने की अनुमति, अधिकार या लाइसेंस नहीं देगी।

(iii) आंध्र प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने पर सहमत होती है कि बेगमपेट, हैदराबाद में स्थित मौजूदा हवाईअड्डे को नागर विमानन गतिविधि के लिए बंद कर दिया जाएगा।

5. संप्रभु प्रतिरक्षा

5.1 संप्रभु प्रतिरक्षा का परित्याग

आंध्र प्रदेश सरकार एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होती है कि उसके द्वारा इस समझौते का कार्यान्वयन, संवितरण और निष्पादन एक संप्रभु कृत्य का गठन नहीं करता है, और यह कि:

(क) यदि इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेन-देन के संबंध में उसके या उसकी संपत्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऐसी कार्यवाही, कार्यान्वयन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से किसी भी संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा उनमें से प्रत्येक द्वारा या उनकी ओर से या उनकी किसी भी संपत्ति के संबंध में नहीं किया जाएगा; और

(ख) कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, आंध्र प्रदेश सरकार संप्रभु प्रतिरक्षा के किसी भी अधिकार का परित्याग करती है, जो उसके पास या उसकी संपत्ति के पास अभी है या भविष्य में किसी भी क्षेत्राधिकार में प्राप्त हो सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके खिलाफ किसी भी निर्णय के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सहमति देती है (जिसमें किसी भी संपत्ति के खिलाफ या उसके संबंध में किसी भी निर्णय या किसी निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश का कार्यान्वयन या प्रवर्तन शामिल है, चाहे उसका उपयोग या इच्छित उपयोग कुछ भी हो)।

5.2 अपवाद

इसमें इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संप्रभु प्रतिरक्षा के किसी भी अधिकार का ऐसा परित्याग

(क) किसी भी कांसुलर या राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास की संपत्ति और परिसंपत्तियों, या

(ख) रक्षा सेवाओं से संबंधित संपत्ति और भारत संघ की परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होगा।

6. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व

प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि:

क. उसके पास इस समझौते का कार्यान्वयन, संवितरण और निष्पादन करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है;

ख. उसने इस समझौते के कार्यान्वयन, संवितरण और निष्पादन को अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है;

ग. यह समझौता इसकी शर्तों के अनुसार इसके खिलाफ लागू करने योग्य इसके कानूनी, मान्य और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है।

7. एचआईएल क्षतिपूर्ति घटनाएं

7.1 एचआईएल क्षतिपूर्ति घटना के घटित होने की स्थिति में, आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएल के लिखित अनुरोध पर, एचआईएल क्षतिपूर्ति घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में इस समझौते के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने में या परियोजना समझौतों

के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने और निष्पादन करने में होने वाली किसी भी लागत, हानि, दायित्व या किसी भी परिणाम से एचआईएएल की क्षतिपूर्ति करेगी और उसे सुरक्षित रखेगी और भुगतान के लिए ऐसे अनुरोध के तीस⁽³⁰⁾ दिनों के भीतर एचआईएएल को निम्नलिखित के कुल योग के बराबर राशि का भुगतान करेगी:

(क) एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना के परिणाम के रूप में एचआईएएल द्वारा उठाई गई सभी अतिरिक्त लागतें और खर्च;

(ख) निम्नलिखित का कुल योग:

(i) रियायत समझौते और या परियोजना समझौतों के अनुसार एचआईएएल द्वारा अपने किसी भी ठेकेदार या उप-ठेकेदार, एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी भी विशेषाधिकार, फ्रेंचाइजी, पट्टे या किसी अन्य अधिकार या उप-अधिकार के परिणामस्वरूप ऐसी एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना के कारण एचआईएएल द्वारा भुगतान की गई या देय सभी राशियां (चाहे जुर्माना, दावों के निपटान या अन्यथा के माध्यम से);

(ii) सभी अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और अन्य राशियां जो एचआईएएल ऐसी एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना के परिणामस्वरूप ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए बाध्य है; और

(iii) ऐसी एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना के परिणामस्वरूप एचआईएएल द्वारा भुगतान की गई या देय सभी अतिरिक्त ओवरहेड्स और परिचालन लागत और खर्च।

(ग) ऐसी एचआईएएल क्षतिपूर्ति घटना के परिणामस्वरूप एचआईएएल द्वारा सही गई लाभ की हानि, लागत, खर्च, दायित्व या क्षति सहित कोई भी हानि।

7.2 पक्षकार सहमत हैं कि इस खंड 7 के तहत क्षतिपूर्ति करने के आंध्र प्रदेश सरकार के दायित्व केवल तभी उत्पन्न होंगे जब देय क्षतिपूर्ति 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) से अधिक हो, और जहां ऐसी क्षतिपूर्ति देय हो जाती है, क्षतिपूर्ति की पूरी राशि देय होगी, न कि केवल 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) से अधिक की राशि।

8. चूक (डीफ़ॉल्ट)

8.1 आंध्र प्रदेश सरकार की चूक (डीफ़ॉल्ट) घटनाएं

निम्नलिखित घटना "आंध्र प्रदेश सरकार चूक (डीफ़ॉल्ट) घटना" का गठन करेगी:

(क) यदि आंध्र प्रदेश सरकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करती है जिसके परिणामस्वरूप रियायत समझौता समाप्त हो जाता है।

8.2 चूक (डीफ़ॉल्ट) के परिणाम

आंध्र प्रदेश सरकार की चूक (डीफ़ॉल्ट) घटना की स्थिति में, एचआईएएल के पास आंध्र प्रदेश सरकार को यह सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटी है और यदि आंध्र प्रदेश सरकार तीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी चूक को ठीक करने में विफल रहती है, तो आंध्र प्रदेश सरकार तीस दिनों की अवधि की समाप्ति

के पंद्रह दिनों के भीतर एचआईएल को आंध्र प्रदेश सरकार चूक राशि का भुगतान करेगी, जिस राशि में से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में खंड 7 के अनुसार एचआईएल को भुगतान की गई राशि के बराबर राशि कम कर दी जाएगी जो कि आंध्र प्रदेश सरकार चूक घटना की ओर ले जाने वाली चूक के समान है।

- 8.3 यदि एचआईएल इस समझौते के खंड 8.2 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो अधिकारों का ऐसा प्रयोग एचआईएल के पास तब तक अर्जित सभी अधिकारों और दायित्वों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा (या जो अधिकार के ऐसे प्रयोग से पहले किसी भी कृत्य या चूक के संबंध में उसके बाद अर्जित हो सकते हैं) और उन प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा जो स्पष्ट रूप से निरंतर दायित्वों का प्रावधान करते हैं या जो अधिकारों के ऐसे प्रयोग या अधिकारों के ऐसे प्रयोग के परिणामों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं।

9. विलंबित भुगतान

यदि इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश सरकार से देय किसी भी राशि का भुगतान एचआईएल की ओर से या उसके लिए अनुरोध के तीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी विलंबित राशियों पर उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की दीर्घकालिक प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा। यदि ब्याज के साथ देय राशि का भुगतान ऊपर बताए अनुसार तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से नब्बे दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो मामला एचआईएल के विकल्प पर, खंड 10 (ख) से (च) के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है और यह एक विवाद का गठन करेगा।

10. सौहार्दपूर्ण समाधान और मध्यस्थता

क. जहां रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से इसके विपरीत न कहा गया हो, पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, अंतर या विवाद, जो इस समझौते के तहत, उससे या उसके संबंध में उत्पन्न होता है, जिसमें किसी भी कृत्य, निर्णय के संबंध में विवाद शामिल है या किसी भी पक्षकार की राय और दूसरे पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित (विवाद), प्रथम दृष्टया भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा। खंड 10 में किसी भी विवाद के उद्देश्य के लिए, "पक्षकार" के संदर्भ का अर्थ एक तरफ एचआईएल और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार होगा और "पक्षकारों" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। यदि विवाद को पूर्वगामी के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाता है, तो कोई भी पक्षकार नीचे दिए गए खंड 10 (ख) से (च) के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

ख. खंड 10 (क) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद जो सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, उसे अंततः भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, और या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे, एक प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरा मध्यस्थ, जो अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा, पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- ग. मध्यस्थता का स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का हैदराबाद शहर होगा। पक्षकारों के समझौते से, यदि आवश्यक हो, तो मध्यस्थता की सुनवाई कहीं और आयोजित की जा सकती है।
- घ. मध्यस्थता के लिए अनुरोध, अनुरोध का उत्तर, संदर्भ की शर्तें, कोई भी लिखित प्रस्तुतीकरण, कोई भी आदेश और फैसले अंग्रेजी में होंगे और यदि मौखिक सुनवाई होती है, तो सुनवाई में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी।
- ङ. मध्यस्थ एक लिखित, तर्कसंगत निर्णय देगा। पक्षकार सहमत हैं कि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाला निर्णय या फैसला पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, और या उसके किसी भी वैधानिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार लागू करने योग्य होगा।
- च. किसी विवाद पर प्रस्तुतीकरण और या निर्णय लंबित रहने तक और जब तक कि मध्यस्थता निर्णय प्रकाशित न हो जाए, पक्षकार ऐसे निर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन के पक्षपात के बिना इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे।

11. संबंधित विवाद

जहां परियोजना के लाभ के लिए पक्षकारों के मध्य किसी विवाद या विवाद के किसी हिस्से को पक्षकारों और परियोजना पर लगे किसी अन्य पक्षकारों के मध्य विवाद या लंबित विवाद के समान मध्यस्थता कार्यवाही में हल किया जाना लाभदायक है (संबंधित विवाद), तब:

(क) आंध्र प्रदेश सरकार, एचआईएएल के उचित अनुरोध पर, एचआईएएल और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य के विवाद को संबंधित विवाद के संबंध में नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों को संदर्भित करेगी और ऐसे संबंधित विवाद के समान समय पर निर्धारित की जाएगी।

(ख) संबंधित विवाद की स्थिति में यह एचआईएएल की उचित राय में परियोजना के लिए लाभदायक है कि इसे उन मध्यस्थों द्वारा हल किया जाए जिन्हें इस समझौते के तहत एचआईएएल और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य का विवाद संदर्भित किया गया है, फिर, आंध्र प्रदेश सरकार सहमत होती है कि ऐसा विवाद, एचआईएएल के उचित विवेक में, उक्त मध्यस्थों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार और एचआईएएल के मध्य उक्त विवाद के निर्धारण के साथ-साथ निर्धारित किया जा सकता है।

12. समाप्ति

यह समझौता रियायत समझौते के साथ सह-समाप्त होगा और रियायत समझौते की समाप्ति पर तुरंत समाप्त हो जाएगा। ऐसी समाप्ति पर, पक्षकारों के सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे। हालांकि, पक्षकारों के वे अधिकार और दायित्व जो ऐसी समाप्ति से पहले अर्जित हुए हैं, ऐसी समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे। इसके अलावा, खंड 10 और 13.11 के प्रावधान भी इस समझौते की समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

13. विविध

13.1 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्षकार लिखित नोटिस द्वारा अपने-अपने अधिकृत प्रतिनिधि को नामित करेगा जिसके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। कोई पक्षकार समान नोटिस द्वारा अपने ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और या बदलने या नया नियुक्ति करने का हकदार होगा।

13.2 नोटिस

इस समझौते के किसी भी पक्षकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भी नोटिस लिखित रूप में होगा और यदि प्रीपेड पंजीकृत डाक या फैक्स द्वारा या किसी डिलीवरी सेवा या कूरियर के माध्यम से प्राप्तकर्ता के पते पर (या जैसा भी मामला हो) वितरित किया जाता है, तो उसे विधिवत तामील माना जाएगा:

आंध्र प्रदेश सरकार को:

संबंधित व्यक्ति का नाम : सचिव, परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
पता : जे-ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद - 500 022
टेलीफोन : +91 40 2345 4591
फैक्स नंबर : +91 40 2345 0108

डेवलपर और एचआईएल को:

संबंधित व्यक्ति का नाम : श्री किरण कुमार ग्रांथि
पता : 6-3-866/1/जी2, ग्रीनलैंड्स, बेगमपेट, हैदराबाद - 500 016
टेलीफोन : +91-40 2341 0191
फैक्स नंबर : +91 40 2341 0184

या इस समझौते के उद्देश्यों के लिए ऐसे अन्य पते पर (या फैक्स नंबरों पर जैसा कि तामील किए जाने वाले पक्षकार ने इस खंड 13.2 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया हो)। फैक्स द्वारा तामील किए गए किसी भी नोटिस के बाद उसके पते पर प्राप्तकर्ता को प्रीपेड पंजीकृत डाक या डिलीवरी सेवा या कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा। प्रीपेड पंजीकृत डाक द्वारा तामील किया गया कोई भी नोटिस पोस्ट करने के सात दिनों (7) बाद तामील माना जाएगा। किसी भी नोटिस की तामील साबित करने में, पत्र के मामले में यह साबित करना पर्याप्त होगा कि ऐसा पत्र उचित रूप से मुद्रांकित, संबोधित और डाक में रखा गया था या वितरित किया गया था या ऊपर दिए गए या इस समझौते के उद्देश्यों के लिए बाद में अधिसूचित प्राप्तकर्ता के पते पर छोड़ा गया था।

13.3 समनुदेशन

पक्षकारों की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते को समनुदेशित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस समझौते के तहत लाभ पक्षकारों की ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना ऋणदाताओं को समनुदेशित किए जाएंगे।

13.4 निहित छूट और संचयी उपाय

इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसार किसी भी पक्षकार में निहित किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का उपयोग करने में कोई कृत्य, या उपयोग करने में विफलता, या देरी, उस पक्षकार द्वारा उस या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय का परित्याग नहीं माना जाएगा। इस समझौते द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और उपाय संचयी हैं और (जैसा कि इस समझौते में अन्यथा प्रदान किया गया है) कानून या इच्छिटी में प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपाय को बाहर नहीं करते हैं।

13.5 पृथक्करणीयता

यदि इस समझौते का कोई भी नियम, शर्त या प्रावधान किसी भी कानून का उल्लंघन माना जाता है, तो उसे इस समझौते से हटा दिया गया माना जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और यह समझौता पूर्ण प्रभाव में रहेगा जैसे कि ऐसा नियम, शर्त या प्रावधान मूल रूप से इस समझौते में निहित नहीं था। इसके बावजूद, इस तरह के विलोपन की स्थिति में, पक्षकार इस तरह से हटाए गए प्रावधान के स्थान पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और संतोषजनक वैकल्पिक प्रावधान की शर्तों पर सहमत होने के लिए सद्भावना से बातचीत करेंगे।

13.6 संशोधन

- I. इस समझौते में कोई भी संशोधन या रूपांतरण तब तक मान्य और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसके पक्षकार सहमत न हों और लिखित रूप में साक्ष्य न दिया गया हो। आंध्र प्रदेश सरकार या एचआईएएल किसी भी समय इस समझौते के किसी भी हिस्से के संचालन की समीक्षा करने के लिए चर्चा में प्रवेश करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पक्षकार पर प्रतिबद्धता के बिना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसे आपसी सहमति से संशोधित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि, जब तक कि ऐसी आपसी सहमति न हो, इस समझौते के प्रावधान (जैसा कि हाल ही में, यदि लागू हो, संशोधित) लागू रहेंगे।
- II. पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के नियम और शर्तें और अनुलग्नकों की पर्याप्तता एचआईएएल और ऋणदाताओं द्वारा समीक्षा के अधीन है, विशेष रूप से क्योंकि इस समझौते की तिथि पर लागू होने वाले अंतिम रूप देना संभव नहीं है जब तक कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट न बनाई जाए और इसलिए नियम और शर्तें परिवर्तन और या अनुपूरक के अधीन हैं। यदि ऐसी किसी समीक्षा के परिणामस्वरूप, परियोजना पर किसी भी प्रतिकूल या अप्रत्याशित प्रभावों को कम करने के लिए या ऋणदाताओं का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिवर्तन, अनुपूरक और या अतिरिक्त समझौतों की आवश्यकता होती है, तो पक्षकार ऐसे परिवर्तनों और या अनुपूरकों के समावेशन या ऐसे अतिरिक्त समझौतों के निष्पादन पर विचार करेंगे और सद्भावना से सहमत होने का प्रयास करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

13.7 प्रतिरूप

यह समझौता दो प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक मूल होगा, लेकिन ऐसे प्रतिरूप या डुप्लिकेट मिलकर एक ही समझौता बनाएंगे।

13.8 कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता, सभी मामलों में, भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और इसके अनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

खंड 10 के अधीन, इस समझौते को लागू करने के लिए या इस समझौते से उत्पन्न होने वाली या इसके संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में, पक्षकार अपरिवर्तनीय रूप से केवल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं और स्थान के आधार पर या इस आधार पर कि कार्यवाही किसी असुविधाजनक मंच पर लाई गई है, ऐसी अदालतों में कार्यवाही के लिए किसी भी आपत्ति का परित्याग करते हैं।

13.9 भाषा

इस समझौते के तहत दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और सभी संचार, दस्तावेज और कार्यवाही, जो किसी भी तरह से इस समझौते से संबंधित हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे। इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा होगी।

13.10 छूट और सहमतियां

(क) इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और निष्पादन में दूसरे पक्षकार द्वारा किसी भी चूक के किसी भी पक्षकार द्वारा परित्याग:

(i) इसके तहत किसी भी अन्य या बाद की चूक या इस समझौते के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के परित्याग के रूप में कार्य या अर्थ नहीं लगाया जाएगा;

(ii) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और ऐसे पक्षकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(iii) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

(ख) किसी भी अवसर पर इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर किसी भी पक्षकार द्वारा जोर देने में विफलता या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई समय या अन्य ढील को इस समझौते के किसी भी नियम, शर्त या प्रावधान के उल्लंघन या परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

13.11 गोपनीयता

(क) इस समझौते के पक्षकारों को रियायत समझौते, परियोजना समझौतों या इस समझौते से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखना चाहिए और कोई भी प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए और अपने कर्मचारियों, एजेंटों और ठेकेदारों को रियायत समझौते, परियोजना समझौतों या इस समझौते से संबंधित या उसकी किसी भी जानकारी, डाटा, दस्तावेजों, रहस्य, सौदों, लेनदेन या मामलों के किसी भी व्यक्ति को प्रकटीकरण करने से रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना चाहिए।

(ख) पक्षकारों का गोपनीयता दायित्व निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:

(i) कोई भी मामला जिसे कोई पक्षकार प्रदर्शित कर सकता है कि वह इस खंड के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अन्यथा आम तौर पर उपलब्ध है और सार्वजनिक डोमेन में है;

(ii) कोई भी प्रकटीकरण जो इस समझौते के तहत उस पक्षकार के दायित्वों के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है;

(iii) जानकारी का प्रकटीकरण जो किसी भी कानून या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या सरकारी या नियामक प्राधिकरण (आयकर विभाग सहित) के नियमों द्वारा आवश्यक है, चाहे कानून का बल हो या न हो (लेकिन, यदि कानून का बल नहीं है तो अनुपालन जिसके अधीन व्यक्तियों के सामान्य अभ्यास के अनुसार है);

(iv) किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण जो खुलासा करने वाले पक्षकार द्वारा इसके प्रकटीकरण से पहले प्राप्त करने वाले पक्षकार के कानूनी कब्जे में है;

(v) ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं या उप-ठेकेदारों को उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक जानकारी का प्रावधान, बशर्ते जानकारी का खुलासा होने से पहले उन पर इस समझौते में निहित गोपनीयता के समान दायित्व लगाए जाएं;

(vi) शेयरधारकों, ऋणदाताओं या ऋणदाताओं के पेशेवर सलाहकारों और बीमा सलाहकारों को जानकारी का प्रावधान;

(vii) रियायत समझौते में अपने दायित्वों के साथ एचआईएएल द्वारा अनुपालन;

(viii) पुलिस आयुक्त को दी गई जानकारी।

(ग) इस खंड में निर्धारित प्रावधान और दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति की स्थिति में यथास्थिति बने और लागू रहेंगे।

13.12 कोई साझेदारी नहीं

इस समझौते में कुछ भी नहीं और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा बनता है, और न ही ऐसे किसी भी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने संबंधित दायित्वों के पक्षकारों द्वारा निष्पादन, पक्षकारों के मध्य एक साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्षकार के पास अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा किसी अन्य पक्षकार को बाध्य करने का कोई अधिकार (जब तक कि इस समझौते के आधार पर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदत्त न किया गया हो और रद्द न किया गया हो) नहीं होगा।

13.13 समय एक महत्वपूर्ण घटक है

इस समझौते में उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी भी तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में समय का विशेष महत्व होगा।

13.14 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय को संदर्भित करेगा। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, अधिनियम, घटना या चूक का दिन जिससे निर्दिष्ट समय अवधि शुरू होती है, शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

13.15 भुगतान स्वच्छ और स्पष्ट होना

इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान (कानून द्वारा आवश्यक सीमा तक या इस समझौते के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत सीमा को छोड़कर) किया जाएगा (क) किसी भी प्रतिबंध या शर्तों से मुक्त; और (ख) सेट-ऑफ या काउंटर-क्लेम के कारण किसी भी कटौती या रोक के बिना।

जिसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने ऊपर लिखे दिन, महीने और वर्ष पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के लिए एवं की ओर से ----- नाम: श्री जे. रामबाबू पदनाम: विशेष मुख्य सचिव, परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए एवं की ओर से ----- नाम: श्री किरण कुमार ग्रांथि पदनाम: निदेशक
साक्षी/गवाह: 1. [हस्ताक्षर] 2. [हस्ताक्षर]	साक्षी/गवाह: 1. [हस्ताक्षर] 2. [हस्ताक्षर]

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 30 सितंबर, 2003

अनुलग्नक 1

आंध्र प्रदेश सरकार की चूक (डीफ़ाल्ट) राशि

1. वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व

वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व देय 'आंध्र प्रदेश सरकार की चूक (डीफ़ाल्ट) राशि', (खंड 8.2 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि पर निर्धारित) एक ऐसी राशि होगी जो निम्नलिखित के कुल योग के बराबर होगी:

(क) केवल ऐसा बकाया ऋण और बकाया ब्याज जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा रियायत समझौते के तहत नहीं किया गया है;

(ख) परियोजना समझौतों और वित्तपोषण समझौतों के तहत सभी हस्तांतरण लागतें, हस्तांतरण कर और आकस्मिक देनदारियाँ;

(ग) परियोजना में भुगतान की गई सभी बकाया इक्विटी, ऐसी इक्विटी लगाए जाने की अवधि के लिए 18.33% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धित।

2. वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात

वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात देय 'आंध्र प्रदेश सरकार की चूक (डीफ़ाल्ट) राशि', निम्नलिखित के कुल योग की राशि होगी:

(क) केवल ऐसा बकाया ऋण और बकाया ब्याज जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा रियायत समझौते के तहत नहीं किया गया है;

(ख) परियोजना समझौतों और वित्तपोषण समझौतों के तहत सभी हस्तांतरण लागतें, हस्तांतरण कर और आकस्मिक देनदारियाँ;

(ग) चूक (डीफ़ाल्ट) की तिथि पर एचआईएल के इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य देय होगा, और इस उचित बाजार मूल्य का निर्धारण किसी ऐसे प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा जिसे पिछले 5 वर्षों में न तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा और न ही एचआईएल द्वारा नियुक्त किया गया हो।

अनुलग्नक 2

ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल), इक्विटी, अग्रिम विकास कोष अनुदान (एडीएफजी) और ऋण निकासी अनुसूची (संचयी)

तिमा ही	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आईए फएल	31 %	42 %	5 0 %	69 %	91 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%

तिमा ही	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इक्किटी	31 %	42 %	50 %	50 %	50 %	58 %	67 %	73 %	82 %	91 %	100 %
ऋण	0%	0%	7 %	7%	7%	15 %	33 %	44 %	62 %	81 %	100 %
एडीए फजी	33 %	33 %	33 %	67 %	67 %	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

टिप्पणी

आईएफएल और इक्किटी को प्रत्येक के 50% तक आनुपातिक (pro-rated) रूप से निकाला जाना है, फिर शेष आईएफएल निकाला जाएगा, और उसके बाद शेष इक्किटी और ऋण निकाला जाएगा।